



भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता: एक तुलनात्मक अध्ययन

Dhurab Kumar Sharma (Research Schoolr)

Prof. (Dr.) Saraswati Ghosh (Research Supervisor)

Department Of Education, Sanskriti University, Mathura, U.P.

सारांश

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन करना तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण के आधार पर दोनों प्रकार के विद्यालयों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना था। प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। अध्ययन की जनसंख्या में राजस्थान के भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित किए गए। उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि द्वारा प्रत्येक तहसील से एक राजकीय एवं एक निजी माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 20 विद्यालयों से 100 शिक्षकों तथा 800 विद्यार्थियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया। अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ कि राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर पाया गया। निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों का मध्यमान राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की तुलना में अधिक पाया गया। इसके अतिरिक्त भौतिक एवं अन्य सुविधाएँ, अधिगम एवं पाठ्यक्रम तथा उपलब्धि एवं मूल्यांकन के आयामों में भी दोनों प्रकार के विद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर प्राप्त हुआ। दूसरी ओर, राजकीय एवं निजी विद्यालयों के शिक्षकों के समग्र प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इसी प्रकार विद्यालय प्रशासन एवं वातावरण, भौतिक सुविधाएँ तथा विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार के आयामों में भी शिक्षकों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ। अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से निजी विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता अपेक्षाकृत बेहतर अनुभव की जाती है,



जबकि शिक्षकों का दृष्टिकोण दोनों प्रकार के विद्यालयों के प्रति लगभग समान है। अध्ययन के निष्कर्ष माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, संसाधनों के सुदृढीकरण तथा विद्यालयी वातावरण के विकास के लिए उपयोगी दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।

मुख्य शब्द: शैक्षिक गुणवत्ता, माध्यमिक शिक्षा, राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, विद्यार्थी प्रत्यक्षण, शिक्षक प्रत्यक्षण, तुलनात्मक अध्ययन, भरतपुर जनपद।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विकास का मूल आधार है। यह केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्यों के विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राष्ट्रीय प्रगति का भी प्रमुख साधन है। किसी भी देश की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यदि शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण होगी तो वह सक्षम, उत्तरदायी एवं सृजनशील नागरिकों का निर्माण करेगी, जो राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा का विशेष स्थान है। यह प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करती है। इसी स्तर पर विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता, तार्किक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यक्तित्व विकास तथा व्यावसायिक अभिरुचियों का निर्माण होता है। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, कौशल विकास तथा रोजगारोन्मुखी जीवन के लिए तैयार करती है। इसलिए इस स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता का सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों एवं उनके भविष्य पर पड़ता है।

वर्तमान समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा नीति एवं अनुसंधान का प्रमुख विषय बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में भी सभी के लिए समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने भी माध्यमिक शिक्षा को अधिक लचीला, बहुविषयक, कौशल-आधारित तथा विद्यार्थी-केंद्रित



बनाने पर बल दिया है। इसके साथ ही विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग, दक्ष एवं प्रशिक्षित शिक्षक, प्रभावी विद्यालय प्रशासन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आवश्यक घटकों के रूप में स्वीकार किया गया है।

शैक्षिक गुणवत्ता एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें विद्यालय की भौतिक एवं अन्य सुविधाएँ, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, पाठ्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन प्रणाली, विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों की दक्षता, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं विद्यालय का समग्र वातावरण सम्मिलित होते हैं। इन सभी घटकों की प्रभावशीलता के आधार पर किसी विद्यालय की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन किया जा सकता है।

राजस्थान राज्य के भरतपुर जनपद में राजकीय एवं निजी दोनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालय बड़ी संख्या में संचालित हैं। यद्यपि दोनों प्रकार के विद्यालय समान पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक उद्देश्यों का पालन करते हैं, तथापि उपलब्ध संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं, शिक्षण पद्धतियों, प्रशासनिक व्यवस्था तथा विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सेवाओं में पर्याप्त भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। सामान्यतः निजी विद्यालयों में आधुनिक अधोसंरचना, तकनीकी संसाधन एवं अनुशासित शैक्षणिक वातावरण अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध होता है, जबकि राजकीय विद्यालयों में व्यापक पहुँच, प्रशिक्षित शिक्षक तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रमुख विशेषताएँ हैं। ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार के विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता का वस्तुनिष्ठ एवं तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

भरतपुर जनपद के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन न केवल वर्तमान शैक्षिक स्थिति को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी बताता है कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष विद्यालयी शिक्षा की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन करने में अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि



दोनों ही शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख हितधारक हैं। विद्यार्थियों के अनुभव विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं मूल्यांकन व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं, जबकि शिक्षकों के प्रत्यक्षण से विद्यालय प्रशासन, संसाधनों तथा शैक्षिक वातावरण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकता है।

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध "भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता: एक तुलनात्मक अध्ययन" शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। इस अध्ययन में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण के आधार पर दोनों प्रकार के विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जिससे माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया जा सके तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उपयोगी सुझाव प्रदान किए जा सकें।

अध्ययन की आवश्यकता एवं औचित्य

वर्तमान समय में शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित न रहकर मानव संसाधन विकास, सामाजिक परिवर्तन तथा राष्ट्रीय प्रगति का प्रमुख आधार बन गई है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी स्तर पर विद्यार्थियों की बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षमताओं का विकास होता है। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगारोन्मुखी जीवन के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इस स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता का निरंतर मूल्यांकन एवं सुधार अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के मध्य शैक्षिक गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, अनुशासन, मूल्यांकन प्रणाली तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों को लेकर व्यापक चर्चा होती रहती है। सामान्यतः यह धारणा प्रचलित है कि निजी विद्यालय अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक वातावरण एवं संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जबकि राजकीय विद्यालयों में अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता अधिक



होती है। इन धारणाओं की वास्तविकता का वस्तुनिष्ठ परीक्षण शोध के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ने विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण अधिगम, समान अवसर, समावेशी शिक्षा, प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग तथा सीखने के परिणामों में सुधार पर विशेष बल दिया है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालयों की वर्तमान शैक्षिक गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए तथा उनकी शक्तियों एवं कमियों की पहचान की जाए। भरतपुर जनपद राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शैक्षिक जिला है, जहाँ राजकीय एवं निजी दोनों प्रकार के माध्यमिक विद्यालय बड़ी संख्या में संचालित हैं। इन विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता, उपलब्ध संसाधनों तथा शिक्षण व्यवस्था में विद्यमान समानताओं एवं भिन्नताओं का व्यवस्थित अध्ययन अपेक्षाकृत कम हुआ है। विशेष रूप से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण के आधार पर दोनों प्रकार के विद्यालयों की गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन स्थानीय स्तर पर अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि विद्यार्थियों का प्रत्यक्षण विद्यालय की वास्तविक शैक्षिक व्यवस्था, अधिगम अनुभव एवं उपलब्ध सुविधाओं का प्रत्यक्ष संकेतक होता है, जबकि शिक्षकों का प्रत्यक्षण विद्यालय प्रशासन, शिक्षण व्यवस्था, संसाधनों एवं विद्यार्थियों के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इन दोनों पक्षों के तुलनात्मक विश्लेषण से माध्यमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति का समग्र चित्र प्राप्त किया जा सकता है।

इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रशासकों, नीति-निर्माताओं तथा शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रभावी योजनाएँ बनाने में सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही यह अध्ययन राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के सुदृढीकरण, विद्यालय प्रशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने तथा विद्यार्थियों के सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाने हेतु उपयोगी सुझाव उपलब्ध कराएगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह अध्ययन न केवल शैक्षिक



दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यावहारिक एवं नीतिगत दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी एवं औचित्यपूर्ण है। प्रस्तुत अध्ययन माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के अनुसंधानों के लिए भी आधार प्रदान करेगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रत्यक्षण के आयामों—भौतिक एवं अन्य सुविधाएँ, अधिगम एवं पाठ्यक्रम तथा उपलब्धि एवं मूल्यांकन—का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रत्यक्षण के आयामों—विद्यालय प्रशासन एवं वातावरण, भौतिक सुविधाएँ तथा विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार—का तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पनाएँ

(H₀₁): भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।



(H₀₂): भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

न्यादर्श

अध्ययन हेतु उद्देश्यपरक न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया गया। भरतपुर जनपद की दस तहसीलों में से प्रत्येक तहसील से एक राजकीय एवं एक निजी माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 20 विद्यालय अध्ययन हेतु चयनित किए गए। प्रत्येक चयनित विद्यालय से 5 शिक्षकों तथा 40 विद्यार्थियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

शोध उपकरण

अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा निर्मित निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया—

1. विद्यार्थी प्रत्यक्षण मापनी
2. शिक्षक प्रत्यक्षण मापनी

सांख्यिकीय तकनीकें

संकलित आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या हेतु निम्नलिखित सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया—

- मध्यमान
- मानक विचलन
- टी-परीक्षण

परिणाम एवं विवेचना

अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण अध्ययन के उद्देश्यों एवं परिकल्पनाओं के अनुसार किया गया। राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के



प्रत्यक्षण की तुलना हेतु स्वतंत्र नमूना t -परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त परिणामों की व्याख्या निम्नानुसार प्रस्तुत है।

शून्य परिकल्पना (H_{01}): भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी 1

राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के समग्र प्रत्यक्षण का तुलनात्मक विश्लेषण

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	निर्णय
राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी	400	23.42	4.67	4.60	परिकल्पना अस्वीकृत
निजी विद्यालयों के विद्यार्थी	400	25.19	6.12		

व्याख्या

सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का मध्यमान 23.42 तथा मानक विचलन 4.67 है, जबकि निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों का मध्यमान 25.19 तथा मानक विचलन 6.12 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त टी-मान 4.60 है, जो 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक मान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है।

इससे स्पष्ट होता है कि राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्षण में सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर विद्यमान है। निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों का औसत प्रत्यक्षण अधिक होने से यह संकेत मिलता है कि वे अपने विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसका कारण



निजी विद्यालयों में उपलब्ध अपेक्षाकृत बेहतर अधोसंरचना, नियमित शैक्षणिक गतिविधियाँ, तकनीकी संसाधनों का उपयोग तथा सतत शैक्षणिक अनुश्रवण हो सकता है।

सारणी 2

विद्यार्थियों के प्रत्यक्षण के विभिन्न आयामों का तुलनात्मक विश्लेषण

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	निर्णय
भौतिक एवं अन्य सुविधाएँ	राजकीय	400	8.74	4.49	2.13	अस्वीकृत
	निजी	400	9.39	4.12		
अधिगम एवं पाठ्यक्रम	राजकीय	400	7.27	4.69	5.71	अस्वीकृत
	निजी	400	8.98	3.72		
उपलब्धि एवं मूल्यांकन	राजकीय	400	9.55	3.97	4.33	अस्वीकृत
	निजी	400	10.68	3.39		

व्याख्या

सारणी 2 से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों के प्रत्यक्षण के तीनों आयामों में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर प्राप्त हुआ। भौतिक एवं अन्य सुविधाओं के आयाम में निजी विद्यालयों का मध्यमान (9.39) राजकीय विद्यालयों (8.74) से अधिक है तथा प्राप्त टी-मान 2.13 सार्थक पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के प्रति विद्यार्थियों की संतुष्टि अपेक्षाकृत अधिक है। अधिगम एवं पाठ्यक्रम के आयाम में राजकीय विद्यालयों का मध्यमान 7.27 तथा निजी विद्यालयों का 8.98 प्राप्त हुआ। प्राप्त टी-मान 5.71 उच्च स्तर पर सार्थक है, जिससे स्पष्ट होता है कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रत्यक्षण अधिक सकारात्मक है। इसी प्रकार उपलब्धि एवं मूल्यांकन के आयाम



में भी निजी विद्यालयों का मध्यमान (10.68) राजकीय विद्यालयों (9.55) से अधिक पाया गया तथा टी-मान 4.33 सार्थक प्राप्त हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि निजी विद्यालयों में मूल्यांकन प्रणाली एवं शैक्षिक उपलब्धियों के संबंध में विद्यार्थियों की धारणा अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक है।

शून्य परिकल्पना (H_{02}): भरतपुर जनपद के राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी 3

राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समग्र प्रत्यक्षण का तुलनात्मक विश्लेषण

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	निर्णय
राजकीय विद्यालयों के शिक्षक	50	27.36	5.41	1.03	परिकल्पना स्वीकृत
निजी विद्यालयों के शिक्षक	50	28.55	6.11		

व्याख्या

सारणी 3 के अनुसार राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों का औसत प्रत्यक्षण (मध्यमान = 27.36, मानक विचलन = 5.41) तथा निजी विद्यालयों के शिक्षकों का औसत प्रत्यक्षण (मध्यमान = 28.55, मानक विचलन = 6.11) प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त टी-मान 1.03 है, जो 0.05 स्तर पर सार्थकता के लिए आवश्यक मान से कम है। अतः दोनों समूहों के मध्य प्राप्त अंतर सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक नहीं है। इस आधार पर शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है तथा यह निष्कर्ष निकलता है कि राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है। यद्यपि निजी विद्यालयों के शिक्षकों का मध्यमान



(28.55) राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों (27.36) की तुलना में थोड़ा अधिक है, किन्तु यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों प्रकार के विद्यालयों के शिक्षक विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण व्यवस्था तथा शैक्षिक वातावरण के संबंध में लगभग समान दृष्टिकोण रखते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि दोनों प्रकार के विद्यालयों के शिक्षक समान पाठ्यक्रम, समान शैक्षिक उद्देश्यों तथा राज्य सरकार एवं शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानकों के अनुरूप कार्य करते हैं।

सारणी 4

शिक्षकों के प्रत्यक्ष के विभिन्न आयामों का तुलनात्मक विश्लेषण

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	निर्णय
विद्यालय प्रशासन एवं वातावरण	राजकीय	50	10.46	2.61	0.10	स्वीकृत
	निजी	50	10.52	3.22		
भौतिक सुविधाएँ	राजकीय	50	9.46	3.60	1.92	स्वीकृत
	निजी	50	8.17	3.09		
विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार	राजकीय	50	8.58	2.33	0.84	स्वीकृत
	निजी	50	8.16	2.67		

व्याख्या

सारणी 4 से स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के प्रत्यक्ष के किसी भी आयाम में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के मध्य सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ। विद्यालय प्रशासन एवं वातावरण के आयाम में राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों का मध्यमान 10.46 तथा निजी विद्यालयों के शिक्षकों का मध्यमान 10.52 प्राप्त हुआ। प्राप्त टी-मान 0.10 सार्थकता स्तर से कम है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों प्रकार के विद्यालयों के शिक्षक विद्यालय प्रशासन, अनुशासन,



नेतृत्व तथा विद्यालयी वातावरण के संबंध में लगभग समान धारणा रखते हैं। भौतिक सुविधाओं के आयाम में राजकीय विद्यालयों का मध्यमान 9.46 तथा निजी विद्यालयों का मध्यमान 8.17 प्राप्त हुआ। यद्यपि दोनों मध्यमानों में कुछ अंतर दिखाई देता है, तथापि टी-मान 1.92 सांख्यिकीय रूप से सार्थक नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के अनुसार उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के संबंध में दोनों प्रकार के विद्यालयों की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार के आयाम में राजकीय विद्यालयों का मध्यमान 8.58 तथा निजी विद्यालयों का मध्यमान 8.16 प्राप्त हुआ। प्राप्त टी-मान 0.84 सार्थकता स्तर से कम होने के कारण यह अंतर भी सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के अनुसार विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, अनुशासन एवं व्यवहार के संबंध में दोनों प्रकार के विद्यालयों की स्थिति लगभग समान है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए—

1. राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षिक गुणवत्ता संबंधी समग्र प्रत्यक्षण में सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर पाया गया। निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रत्यक्षण राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक पाया गया।
2. विद्यार्थियों के प्रत्यक्षण के आयामों—भौतिक एवं अन्य सुविधाएँ, अधिगम एवं पाठ्यक्रम तथा उपलब्धि एवं मूल्यांकन—में भी राजकीय एवं निजी विद्यालयों के मध्य सार्थक अंतर प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि इन आयामों के संबंध में निजी विद्यालयों के विद्यार्थी अपेक्षाकृत अधिक संतुष्ट हैं।



3. राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समग्र प्रत्यक्षण में कोई सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ। दोनों प्रकार के विद्यालयों के शिक्षकों ने शैक्षिक गुणवत्ता के संबंध में लगभग समान दृष्टिकोण व्यक्त किया।
4. शिक्षकों के प्रत्यक्षण के आयामों—विद्यालय प्रशासन एवं वातावरण, भौतिक सुविधाएँ तथा विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं व्यवहार—में भी कोई सार्थक अंतर प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षकों के अनुसार दोनों प्रकार के विद्यालयों की कार्यप्रणाली एवं शैक्षिक वातावरण में उल्लेखनीय अंतर नहीं है।
5. अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष अनुभव विद्यालय की शैक्षिक गुणवत्ता का महत्वपूर्ण संकेतक है, जबकि शिक्षकों का दृष्टिकोण अधिक व्यावसायिक एवं संतुलित होने के कारण दोनों प्रकार के विद्यालयों के प्रति लगभग समान रहा।

सुझाव

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत एवं शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अधिगम वातावरण प्राप्त हो सके।
- विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ एवं क्षमता-विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, जिससे वे नवीन शिक्षण पद्धतियों एवं मूल्यांकन तकनीकों का प्रभावी उपयोग कर सकें।
- विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप गतिविधि-आधारित, अनुभवात्मक एवं विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए।



- विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा विद्यार्थियों को समय-समय पर रचनात्मक प्रतिपुष्टि (Feedback) प्रदान की जाए।
- विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समुदाय के मध्य समन्वय स्थापित कर विद्यालयी वातावरण को अधिक सहयोगात्मक एवं उत्तरदायी बनाया जाए।
- शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय एवं निजी विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए तथा गुणवत्ता मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ।

संदर्भ सूची

- अग्रवाल, जे. सी. (2021). *शैक्षिक अनुसंधान का परिचय*। आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
- भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020*। नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।
- बेस्ट, जे. डब्ल्यू, एवं कान, जे. वी. (2019). *Research in Education* (10th ed.). New Delhi: Pearson Education.
- बुच, एम. बी. (2016). *भारतीय शिक्षा में अनुसंधान का सर्वेक्षण*। नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT)।
- कोठारी, सी. आर. (2019). *Research Methodology: Methods and Techniques* (3rd ed.). New Delhi: New Age International Publishers.
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2022). *विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता एवं अधिगम परिणामों पर राष्ट्रीय प्रतिवेदन*। नई दिल्ली: NCERT।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2023). *National Achievement Survey (NAS) 2021: State Report – Rajasthan*. New Delhi: NCERT.
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT). (2023). *Quality Monitoring Tools for Schools*. New Delhi: NCERT.



- शिक्षा मंत्रालय. (2021). *Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) 2020–21 Report*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- शिक्षा मंत्रालय. (2022). *Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) 2021–22 Report*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
- शर्मा, आर. ए. (2020). *शिक्षा अनुसंधान एवं सांख्यिकी*। मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।
- सिंह, आर. पी. (2021). *माध्यमिक शिक्षा: सिद्धांत एवं व्यवहार*। जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?* Paris: UNESCO.
- UNICEF. (2021). *The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health*. New York: UNICEF.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- World Bank. (2022). *The State of Global Learning Poverty: 2022 Update*. Washington, DC: World Bank.
- Yadav, S., & Singh, R. (2021). Quality of Secondary Education in Government and Private Schools: A Comparative Perspective. *Journal of Educational Studies*, 19(2), 45–57.
- Kumar, A., & Sharma, P. (2022). School Infrastructure and Students' Learning Outcomes at Secondary Level. *International Journal of Educational Research*, 11(3), 78–89.
- Mishra, V., & Verma, S. (2023). Teaching-Learning Environment and School Quality: A Comparative Study of Secondary Schools. *Journal of Indian Education*, 49(1), 62–75.
- UNESCO Institute for Statistics. (2022). *Education Data Release: Monitoring Progress Towards SDG-4*. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.

